

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुँच प्रदान करने के लिये तीन वर्ष के लिये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना को मंजूरी दी है।

- ONOS योजना का समन्वय सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है।
- पारंपरिक शैक्षणिक प्रकाशन 'पे टू रीडर' मॉडल पर निर्भर करता है, जहाँ पुस्तकालय और संस्थान प्रकाशित शोध तक पहुँच के लिये शुल्क का भुगतान करते हैं।
- ONOS का उद्देश्य पूरे भारत में छात्रों और शोधकर्त्ताओं के लिये उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना है, जिससे विशेष रूप से टयोर-2 और टयोर-3 शहरों में रहने वाले लोगों को लाभ पहुँचेगा।
- ONOS 30 अग्रणी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक उच्च-प्रभाव वाली पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करेगा, जिससे छात्रों और शोधकर्त्ताओं के लिये शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
 - यह पहल 6,300 से अधिक संस्थानों को लक्षित करती है, जिससे लगभग 1.8 करोड़ छात्र, संकाय और शोधकर्त्ता लाभान्वित होंगे तथा अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं तक पहुँच बढ़ेगी, जिससे वैश्विक अनुसंधान समुदायों में भारत का प्रभाव बढ़ेगा।
- अनुसंधान एवं विकास से संबंधित अन्य पहल:
 - अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023
 - विज्ञान धारा योजना
 - राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF)

और पढ़ें: विज्ञानिक प्रकाशन से संबंधित चर्चाएँ